

include cooks is not abnormal as it did not show a statistically significant difference. No special steps for prevention of this disease amongst the army Cooks are, therefore, considered necessary. If, during the routine monthly medical check-up, an army Cook is suspected to be suffering from this disease, he ceases to be employed on cooking duties; his case is fully medically investigated and he is given either "outdoor-patient" treatment or hospitalised, as necessary.

Naming of Disputed Area in Jammu and Kashmir as Thako Chok

5367. SHRI S. C. SAMANTA: Will the Minister of DEFENCE be pleased to state:

(a) whether in the joint statement issued in Lahore (Pakistan) at the conclusion of the bilateral talks between the Chiefs of Army Staff of India and Pakistan in connection with the dispute of the delineation of line of control in Jammu and Kashmir, the disputed piece of land has been referred to as 'Thako Chok',

(b) the original name of the piece of land;

(c) whether the Indian Chief has not accepted the name "Thako Chok" which the Pakistan side has been referring and which appears to be correct; and

(d) the latest developments with regard to the settlement of the dispute?

THE MINISTER OF DEFENCE (SHRI JAGJIVAN RAM): (a) The disputed area is referred to as 'Thako Chak' in the joint statement.

(b) The original name as mentioned in revenue records is 'ठको चक' (Thako Chak)

(c) The Pakistan side initially called the place Tahkko Chak; but in the joint statement the place was referred to as Thako Chak.

(d) The area has already been vacated by Pakistani troops.

Delay in Appointments to Indian Missions Abroad

5368. SHRI S. C. SAMANTA: Will the Minister of EXTERNAL AFFAIRS be pleased to state:

(a) the reasons for delay in appointments of Diplomats, Heads of Missions and Ambassadors to various countries where the vacancies exist;

(b) the number and places of vacancies awaiting Government's decision for appointments; and

(c) the time by which the task of such appointments is likely to be completed?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRI SURENDRA PAL SINGH): (a) There is no deliberate delay in the appointments of our Heads of Missions, Ambassadors and other senior ranking diplomats to various countries. After appointment the officer needs to take leave or to have briefings and consultations and complete formalities. All this takes time.

(b) and (c). The following vacancies exist in our Missions abroad, where appointments have not been made;

1. London (United Kingdom) — High Commissioner
2. Phnom Penh (Cambodia) — Ambassador
3. Muscat (Oman) — Ambassador
4. Peking (China) — Ambassador

In filling the above vacancies the Foreign Minister and Prime Minister have to exercise their discretion. The matter is under Government's consideration.

गैर-सरकारी उद्योगों में मजदूरों के बारे में
स्थायी नियम

5369. श्री जूलचन्द डाना : क्या
श्री वृन्चोस मंत्री यह बताने की कृपा
करेंगे कि :

(क) क्या प्रत्येक गैर-सरकारी उद्योग
काम चलाने के लिए अपने मजदूरों के लिए
अलग-अलग स्थायी नियम बनाना है ;

(ख) क्या इन नियमों को मजदूरी पर लागू करने से पूर्व संबंधित राज्यों के अम विभागों द्वारा इनकी जांच की जाती है तथा इनका अनुमोदन किया जाता है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या वे गैर-सरकारी उद्योग अपने नियमों में किए गए परिवर्तनों के बारे में अपने-अपने राज्यों के अम विभागों को सूचित करते हैं , और

(घ) क्या संबंधित राज्यों के अम विभाग के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसे नियमों से कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता ?

अम और पुनर्वास मंत्री (श्री श.रं. के. खांडेलकर) : (क) और (ख) औद्योगिक नियोजन (स्थायी आदेश) अधिनियम, 1946 के अनुसार औद्योगिक प्रतिष्ठानों के नियोजकों के लिए उचित सरकार द्वारा नियुक्त किए गए प्रमाणक अधिकारियों द्वारा स्थायी आदेशों को प्रमाणित कराना अपेक्षित है। अधिनियम उचित सरकार द्वारा आदेश स्थायी आदेश तैयार करने और उन परिस्थितियों की भी व्यवस्था करता है जिनमें उन प्रतिष्ठानों में जहां प्रमाणित स्थायी आदेश नहीं है, आदर्श स्थायी आदेश लागू होंगे।

(ग) और (घ) अधिनियम प्रामाणित स्थायी आदेशों से सुधार हेतु अपनायी जाने वाली पद्धति निर्धारित करता है। इस पद्धति के अनुसार, सुधारों को प्रमाणक अधिकारियों द्वारा प्रमाणित किया जाना है। नियोजक उनमें एक पक्षीय रूप से सुधार नहीं कर सकता। प्रमाणित स्थायी आदेशों में नियोजकों और श्रमिकों के बीच समझौते द्वारा भी सुधार किया जा सकता है।

गाडोलिया लूहारों की इस्पात की सप्लाई

5370. श्री मूलबन्ध डाला : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या देश में आज भी गाडोलिया लूहार लाखों की संख्या में है ,

(ख) क्या वे परम्परा से अपने हाथों से लोहे की बनी वस्तुओं की मरम्मत करने है तथा दैनिक जीवन के उपयोग में आने वाली लोहे की छोटी मोटी वस्तुएं बनाते है ,

(ग) क्या सरकार ने इन घरेलू उद्योग धंधों को जीवित रखने के लिए तथा गाडोलिया लूहारों की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए उन्हें इस्पात सप्लाई करने की कोई व्यवस्था की है , यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है , और

(घ) यदि हा, तो उन्हें किस आधार पर कितना इस्पात सप्लाई दिया जाता है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खाँ) : (क) से (घ) सम्प्रदाय क्रम में न तो आबटन किए जाते है और न आकड़े ही रखे जाते हैं फिर भी यह बता दिया जाये कि लघु उद्योग एकको को सप्लाई अपने-अपने लघु उद्योग निगमों के माध्यम से की जाती है और प्रत्येक लघु उद्योग एकको को कारपोरेशन से सम्पर्क स्थापित करना पड़ता है। सम्बन्धित उद्योग निदेशक की सिफारिश पर मुख्य उत्पादकों के स्टाकयाइडों से भी लघु उद्योग एकको को थोड़ी मात्रा में सप्लाई किया जाता है।